**The Health Security Se National Security Cess Bill, 2025 -Contd-passed**

माननीय सभापति **:** मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय कम है, जिन-जिन माननीय सदस्यों को बात रखने के लिए बुलाया जाता है, वे अपनी बात 5 मिनट में रखें ।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल ।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल **(**वलसाड**) :** माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं इसके साथ हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना विजनरी बिल जो हमारी भारत की सुरक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, ऐसा बिल लेकर आए, तो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

सभापति जी, हमारा भारत देश वर्ष 2014 तक विश्व की 11 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 11 साल में ही भारत की अर्थव्यवस्था 11 वीं से 4 वीं नम्बर की बना दी है । हमारा वर्ष 2047 में विकसित भारत का संकल्प है । विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, वह हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा । यह बिल इसको सुनिश्चित करेगा । यह जो नया कानून देश के लिए आ रहा है, यह सुरक्षा और हमारी सेहत के लिए पैसे इकट्ठा करने का इंतजाम करता है । अभी तक जब कोई मुसीबत आती थी, तब हमारी सरकार पैसे खोजने जाती थी, लेकिन इस बिल के जरिये एक परमानेंट फंड बनेगा, जिससे जब कोई भी विपत्ति आएगी या कोई भी इमरजेंसी आएगी, तो स्वास्थ्य के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए यह फंड रहेगा । यह बिल एक ऐसा फंड बनाएगा, जो हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहेगा । पहले की यूपीए सरकार में जब कोई भी इमरजेंसी आती थी, तब वह पैसे खोजने जाती थी, लेकिन यह जो बिल आया है, इसमें ये जो संकट थे, वे सारे संकट यह बिल मिटाएगा ।

सभापति जी, हमारे देश में कैंसर की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत चिंतित थे, इसीलिए परसो जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें सिगरेट पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है और यह जो बिल आया है, वह विशेषकर जो पान, मसाला, गुटखा है उस पर सेस लगाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है, जिसके जरिये हमारी देश की सुरक्षा और हेल्थ पर तो हम लोग पैसे खर्च करेंगे ही, लेकिन हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक मजबूत कदम उठा रहे हैं ।

**15.00 hrs**

एक दुष्प्रचार भारत भर में चल रहा है कि यह बिल आम लोगों पर बोझ बनने वाला है । यह बिल आम लोगों पर बोझ बनने वाला नहीं है । सिर्फ और सिर्फ जो सिन गुड्स हैं, जैसे पान मसाला पर ज्यादा एक्साइज लगाने का इसमें प्रावधान किया गया है । अभी तक जो सेस लगता था, एक्साइज लगता था, टैक्स लगता था, वह बिक्री पर लगता था । बिक्री में अंडर रिपोर्टिंग होती थी, इसलिए टैक्स चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती थी । हम जो नया

कानून ला रहे हैं, उसमें मशीन की क्या कैपेसिटी है, मशीन कितना उत्पादन कर रही है, उस पर टैक्स लगेगा । हम लोग इंस्पेक्टर राज से हटकर एकदम अच्छे से टैक्स कलेक्ट पाएंगे । इसका प्रावधान इस बिल में है ।

पहलगाम और दिल्ली जैसी जब घटनाएं हुईं, तब पता चलता है कि खतरे बदल रहे हैं । जो हमारे विरोधी देश हैं, वे भी अलग-अलग तरह से खतरे पैदा कर रहे हैं । आपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत देश के सुरक्षा बलों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मुकाबला किया । यह बिल सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि बिल के जरिए जितना भी पैसा आएगा, वह हमारे देश की सुरक्षा में लगेगा । जो पुरानी सरकार में कमियां थीं, इस बिल ने उसे ठीक करने का काम किया है ।

मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने, उसके बाद वे आयुष्मान भारत स्कीम लाए । इसके अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होने लगा है । अपोजीशन से सुप्रिया सुले जी ने बोला कि दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं । मैं कहना चाहूंगा कि दवाइयों के दाम बढ़े नहीं हैं, बल्कि कम हुए हैं । मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद खोले गए जनऔषधि केंद्रों में रियायती दामों पर दवाइयां मिल रही हैं, इसलिए यह पूरा दुष्प्रचार है । हमारे जो बुजुर्ग है, उनके लिए पीएमजेएवाई में चालीस लाख बुजुर्गों को जोड़कर स्कीम का लाभ दिया गया है । हमारे देश में इससे 8.25 लाख करोड़ रुपये की बचत लोगों को हुई है । आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों और शहरों में खोले गए हैं । हमारे हेल्थ बजट में वृद्धि हुई है । यह वर्ष 2014 तक सिर्फ 1.15 पर्सेंट था, वह बढ़कर 1.84 पर्सेंट हो गया है । पूरे भारत देश के अंदर अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाया गया है और ज्यादा एम्स हॉस्पिटल्स खोले गए हैं । सबसे महत्पूर्ण है कि साइंस कॉलेजेज़ और मेडिकल कॉलेजेज़ में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2014 के बाद प्रधान मंत्री मोदी जी ने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, बार्डर सुरक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बजट दिया, बल दिया । इसके कारण ही मोदी सरकार ने रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये कर दिया । यह काम हमारे मोदी जी ने किया है । यह जो बिल आएगा, उसका बड़ा हिस्सा हथियार और नई टेक्नोलॉजी खरीदने में जाएगा । हम लोग बार्डर पर जो सड़क और सुरंगें बना रहे हैं, उसमें भी तेजी आएगी । यूपीए सरकार के डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी जी ने बताया था कि हमने देश के बार्डर पर सुरक्षा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया, कोई बजट नहीं दिया । यह जो बिल है, इसमें हमारे बार्डर की सिक्योरिटी है । यह इसको सशक्त करने का काम करेगा । यह टैक्स चोरी रोकने का पक्का इलाज है । यह बिल उद्योगों को ठीक तो करेगा, साथ ही जो टैक्स चोरी कर रहे थे, उनको भी पकड़ेगा । अधिकारी की मर्जी से नहीं, कंपनी की मर्जी से नहीं, बल्कि कंपनी की कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी और स्पीड के हिसाब से टैक्स लगेगा ।

यह बिल लांग टर्म प्लानिंग के लिए है । यह स्थायी समाधान देगा । हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है, आत्मनिर्भर भारत है, ऐसे बड़े मिशन की तरह यह खास काम करेगा । धारा 5 में यह टैक्स का आधार होगा कि मशीन कितनी तेजी से काम करती है । (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल **(**दमन और दीव**) :** माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे "स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया ।

आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे सभी विकसित दृष्टि से मजबूत देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हैल्थ सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है इसलिए सरकार का यह कदम सैद्धांतिक रूप से स्वागत योग्य है । हमें सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, किंतु मंशा से ज्यादा जरूरी है कि सही नीति और उसका प्रभावी इम्पलीमेंटेशन हो ।

भारत में हर साल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की असमय अकाल मृत्यु हो रही हैं । डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि मुंह के कैंसर के 90 प्रतिशत से अधिक मामले स्मोकलेस तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी आदि के सेवन से होते हैं । केवल वर्ष 2022 में ही स्मोकलेस तंबाकू से लगभग 80,000-85000 मुंह के कैंसर के नए मामले सामने आए थे । तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं, हृदय रोग, सीओपीडी, क्षय रोग और अनेक संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा देता है । यह केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं बल्कि भारतीय लोगों एवं आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है । क्या केवल कीमत बढ़ा देने से यह महामारी रुकेगी? हम सब जानते हैं कि नशा शौक नहीं है बल्कि एक लत है । अगर इसकी लत लग जाए तो आदमी पेट्रोल की गंध सूंघ लेता है, आयोडेक्स मल लेता है और कफ सिरप भी पी लेता है । दवा की दुकान पर कौरेक्स खरीदने के लिए आधार कार्ड माँगे जाने के बावजूद भी लोग जुगाड़ कर लेते हैं । गुटखा, पान मसाला पर सेस या जीएसटी बढ़ाने मात्र से क्या हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग इस का सेवन करना छोड़ देंगे?

महोदय, हमने देखा है कि नशे की तलब इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है । इस लत के कारण बच्चे की दूध की बोतल के पैसे, पत्नी के गहने, घर का राशन- सब बिक जाता है । क्या हम इतने भोले हैं कि यह मान लें कि महंगा होने से नशा करने वाले लोग नशे का सेवन करना छोड़ देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जन-स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि हम जहर बेचने की इजाजत दे दें, उस पर टैक्स लगा कर राजस्व कमाएँ और फिर उसी राजस्व से उसी जहर से हुई बीमारी का इलाज करें? क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा है या स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर एक क्रूर मजाक है ?

महोदय, हमारी सरकार का सिद्धांत कभी भी राजस्व के लिए जीवन से समझौता करना नहीं है । मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस सेस बिल को वापस लिया जाए और इसके स्थान पर एक व्यापक, सख्त और वैज्ञानिक कॉम्प्रिहेन्सिव तम्बाकू और गुटखा कंट्रोल बिल लाया जाए जिसमें ये प्रावधान अनिवार्य होने चाहिए, जैसे - सभी तंबाकू उत्पादों (स्मोकिंग एवं स्मोकलेस दोनों) कंपनियों के विज्ञापन, प्रयोजन एवं प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि कोई इलायची तथा अन्य पदार्थों के नाम पर पान मसाला जैसे जहरीले पदार्थ न बेच सके । पैकेट के आगे और पी 90 प्रतिशत हिस्से पर ग्राफिक हैल्थ वॉर्निंग अनिवार्य हो । सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो । 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचने पर कड़ी सजा हो एवं दुकान का लाइसेंस रद्द हो । तंबाकू कंपनियों पर "सुपर प्रॉफिट टैक्स" या "विंडफॉल हैल्थ सेस" लगाया जाए और आम उपभोक्ता पर बोझ न डाला जाए । राजस्व की जरूरत है तो अवैध तंबाकू कारोबार पर कड़ी कार्यवाही कर छिपे हुए हजारों करोड़ रुपये वसूल किए जाएँ ।

महोदय, केवल प्रतिबंध से ही काम नहीं चलेगा । हम सब जानते हैं कि आज भी गली-गली मेंड्रग्स, हेरोइन, चरस और गांजा मिलने की बात होती है । हमारे पड़ोस में गुजरात में शराबबंदी है फिर भी शराब आसानी से हर गली और हर मोहल्ले में मिल जाती है । मजे की बात है कि गुजरात में शराब के सेवन के लिए कानूनी परमिट मिल जाता है और अभी 77 होटलों को शराब परोसने के लाइसेंस भी दिए गए हैं । गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब सेवन की छूट दी जाती है । यह कैसा प्रतिबन्ध है? वहां दारू बिकती है, परमिट मिलता है लेकिन वहां फिर भी दारूबंदी है । आज गुजरात में शराब के रेवेन्यू का 25,000-30,000 हजार करोड़ रुपये का काला कारोबार फलफूल रहा है । इससे अच्छा है कि गुजरात में नियंत्रित बिक्री को वैध कर राजस्व लिया जाए, कम से कम वह पैसा भ्रष्ट तंत्र की तिजोरी में जाने के बजाय सरकारी तिजोरी में आएगा । जब सरकार ने नशे से राजस्व कमाने की ठान ही ली है तो गुजरात सहित देश के बाकी राज्यों में, जहाँ शराब पर पाबंदी लगाई गई है, पूरी तरह से हटा दिया जाये ताकि शराब का काला कारोबार खत्म हो और सरकार को रेवेन्यू मिल सके ।

माननीय सभापति**:** अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल**:** सभापति जी, मानसून सत्र में एक भी बिल पर चर्चा नहीं हुई थी । कृपया आप मुझे कम से कम 30 सेकिंड का समय तो दीजिए । (व्यवधान)

महोदय, वैसे भी जब ऐसे जहरीले नशीले पदार्थों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है तो शराब पर क्यों रहे? जब हम विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते है तो हमें विकसित राष्ट्र की तरह सोचना भी होगा । मेरा मानना है की केवल प्रतिबन्ध से ही कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रतिबन्ध कभी-कभी भ्रष्टाचार का बड़ा दरवाजा खोल देता है और काले कारोबार, काले धन का साम्राज्य खड़ा कर देता है ।

सेस से नहीं, संकल्प से स्वस्थ बनेगा भारत ।

टैक्स से नहीं, तत्परता से सशक्त बनेगा भारत ।

सभापति जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को वापस लेकर एक मजबूत, बहुआयामी तंबाकू नियंत्रण कानून लाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को यह कहना न पड़े कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ।

श्री हनुमान बेनीवाल **(**नागौर**) :** सभापति महोदय, आपने मुझे गुटखा और पान-मसाला उद्योग की सख्त निगरानी के लिए इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, हमने बहुत से माननीय सदस्यों की बात सुनी है । इस बिल पर दो दिन से लगातार चर्चा हो रही है । निश्चित रूप से सरकार कोई भी बिल लाती है, लेकिन कानून बनने के बाद सरकार उस कानून की कितनी पालना करवा सकती है, यह महत्वपूर्ण है । मुझसे पूर्व सांसद ने अपने भाषण के दौरान बताया है कि कई राज्यों में शराबबंदी है, फिर भी वहां शराब बिक रही है । कई राज्यों ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी वहां गुटखा बिक रहा है । सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, इसको पीने से कैंसर हो सकता है । दुर्भाग्य से कानून बनने के बाद भी धरातल पर उन कानूनों की पालना नहीं होती है ।

महोदय, मेरा एक आग्रह है । मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है । इस बिल का मकसद स्वास्थ्य नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है । सरकार ऐसा कह रही है । सेस उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा और कानून के उल्लंघन पर पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान होगा । मैं चाहता हूं कि आप पांच साल की कैद की सजा को बढ़ाकर सात साल कर दें । जब मैं इस विधेयक को पढ़ रहा था, इसमें सरकार ने यह कहा है कि पान-मसाला उत्पादन में मशीनरी और प्रक्रियाओं के उपकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है ।

सभापति महोदय, चूंकि यह बिल वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, मगर जब बात गुटखे और पान मसालों की हो रही है, तो लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इस सदन को गहनता से विचार करने की आवश्यकता है । पान-मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं के उपयोग से लाखों लोग कैंसर सहित कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं । कोटपा जैसे कानून में लिखा है कि सार्वजनिक स्थलों पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है । आप सरकारी दफ्तरों के हालात देखिए । बस स्टेशस, रेलवे स्टेशस, आप जहां कहीं भी जाइए, वहां की दीवारें पान-मसालों की थूक से

रंगी हुई हैं । जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेजेज़ और स्कूल्स हैं, उनके 500 मीटर के दायरे के भीतर अवैध तरीके से दुकानें और ढाबे खुले हुए हैं ।

माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इस सदन के समक्ष एक सकारात्मक दृष्टिकोण से यह बिल प्रस्तुत किया होगा । मैं उनका ध्यान एक विषय की ओर दिलाना चाहूंगा । आज इस सदन में पान-मसालों से होने वाले नुकसान पर तो चर्चा हो रही है, हमारे देश में जो लोग पान-मसालों का प्रचार कर रहे हैं, आपने उन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है । फिल्म अभिनेता शाहरूख खान, अजय देवगन, सलमान खान जैसे कई लोग पान-मसालों का प्रचार करते हैं । ठीक है, प्रचार करना उनका काम है । मगर मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अगर सरकार ने उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, तो सरकार उन अभिनेताओं से राष्ट्रीय पुरस्कार वापस ले । एक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाला अभिनेता गुटखे और पान-मसाले का प्रचार कर रहा है । आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए । उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, अगर वह गुटखे और पान-मसाले का प्रचार करेगा, तो उससे राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिया जाए ।

महोदय, भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े ऐसे मामलों के संबंध में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर और जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट में इन अभिनेताओं के खिलाफ ऐसे मामले लंबित है । मेरे संज्ञान में यह जानकारी मीडिया के माध्यम से आई है । मैं राजस्थान की बात करूं या देश के अन्य राज्यों की बात करूं, धड़ल्ले से अवैध गुटखों की फैक्ट्रियों का संचालन सरकारी तंत्र की मिलीभगत से हो रहा है । कहीं पर भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस विधेयक में आपने सजा का जो प्रावधान रखा है, उसको बढ़ाया जाए । मसाला कंपनियों के मालिकों को कैसे दंडित किया जाए, इस विधेयक में उसका भी प्रावधान किया जाए । देश में कैंसर जैसी घातक बीमारी का बहुत बड़ा कारण गुटखा और पान-मसाला है । इसलिए सरकार को सख्त निगरानी के लिए कोई तंत्र बनाना चाहिए ।

महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । आज देश में इस बात की चिंता की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में जो कंपनियां कार्यरत हैं, जैसे उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की सीएसआर की राशि को कृषि के क्षेत्र में किसानों के भले के लिए व्यय नहीं की जाती है । यह कहा जाता है कि सीएसआर फंड से खर्च किय जाएगा । मंत्री जी, इस बिल से जो राजस्व प्राप्त होगा, क्या सरकार उस राजस्व का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करेगी? आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें ।

मंत्री महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद गुटखा और पान-मसाला के उत्पाद की दरों में बढ़ोतरी होगी । ऐसे में पान-मसालों के उत्पाद में ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी और नकली उत्पादों की भी बढ़ोतरी होगी । आज भी हजारों फैक्ट्रियां नियम और कानून का पालन नहीं कर रही हैं । आप उन पर सख्ती करिए और इस बात को सुनिश्चित करिए कि इस बिल के लागू होने के बाद पान-मसालों की बिक्री में ब्लैंकमेलिंग नहीं होगी ।

श्री किशोरी लाल **(**अमेठी**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सरकार इससे स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक कदम बता रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बिल न तो स्वास्थ्य में सुधार की गारंटी देता है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई प्रत्यक्ष बल प्रदान करता है । इसका मूल उद्देश्य सिर्फ केन्द्र सरकार को एक विशाल राष्ट्रीय संग्रह का तंत्र देना है ।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पहले से जो सेस लगे हुए हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है । जैसे सीएंडएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हजारों-करोड़ रुपयों के सेस अपने निर्धारित फंड में कभी ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं ।

सेंकेड्री एंड हायर एजुकेशन सेस के 94.36 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही पड़े रहे । उसे आपने सही खाते में कभी नहीं पहुंचाया । विभिन्न सेस और सरचार्ज के 3.69 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं, जिनका कोई भी उचित हिसाब नहीं है । जब पुराना पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, तो जनता पर एक नया सेस लगाने की क्या जरूरत है? उसके बाद वास्तविक चिंता यह है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय आज भी जीडीपी के 1.1 से 1.5 प्रतिशत के बीच ही हो रहा है, जबकि वास्तविक लक्ष्य 2.5 प्रतिशत था । सरकार इनके उपायों के बजाय इस सेस को ही समाधान मान रही है, जबकि अभी अस्पतालों की जरूरत है और एम्स की जरूरत है । वहां स्टाफ नहीं हैं और संसाधन भी कम हैं ।

माननीय सभापति **:** कृपया आप अपनी बात को कन्क्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

श्री किशोरी लाल **:** महोदय, मैं अंत में इस सदन में साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह बिल राज्यों की वित्तीय आज़ादी को खत्म करता है, उद्योगों और रोज़गार पर हमला करता है, पारदर्शिता को कम करता है, पहले के सेसेज़ की गड़बड़ियों को ढकने का प्रयास करता है, जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाता है और केन्द्र को असीमित शक्तियां देकर लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है। अंत में मेरा यही कहना है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए ।

**SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR):** Hon. Chairman Sir, the Health Security Se National Security Cess Bill is named in such a way that nobody can object to it as there can be no objection to health security or national security. But the devil lies in the details. We also had a lot of discussions and many of us were discussing about this Bill and it is going to serve its purpose. When we read this Bill, I was very curious to see what kind of national security and health security mentioned in the Bill and it is given in sub-clause (7) of Section 3 in which the purpose is completely delegated.

The Central Government may specify such activities, schemes and programmes for national security or as the case may be for public health as may be prescribed. So, there is no clarity about what national security scheme is and what health security sheme is. This has to come through delegated legislation.

Secondly, if we see what kind of items the cess is laid on there is a provision in Clause 34. In Schedule 1, there is pan masala. Along with that, there is also a provision for the Government to add any more goods and that any more goods is through a notification. That is not going to come under Parliamentary control. In

Clause 34(2), it says that every notification issued under this sub-section shall come to the Parliament as soon as possible. Now, what is this as soon as possible?

Sir, the point I am trying to make in this Bill is the cess, which is a complete blank cheque being asked from the Parliament. There is no clarity in this Bill. There is so much of delegated legislation. Any product could be added through a notification and any changes could be through subsequent delegated legislations.

I also want to seek one clarification. In the last Bill, when I was talking about the Bill, I think, in the reply, hon. Finance Minister has taken my name multiple times regarding my statement on the floor of the House about the compensation cess being extended for three years due to Central Government owned loans.

My intention was very clear. There is a context to this. When there was a shortfall, the Centre asked the State to take a loan. Non-BJP States said we will not take the loan and for that, the Centre had to take a loan. So, it is Centres own loan. It is a fact stated by hon. Finance Minister. I again reiterate the fact if there is any change in that. So, I was not mentioning any unrelated loans. It will be very childish for me to say such things. So, I want to reiterate this fact also.

In this entire Bill, there are sections which are so harsh. If you see the penalties and criminalization, they are five years and after that, there is a presumption of culpability and culpable mental state. Previously I saw this clause in PMLA. Why such harsh penalties are there in this Bill? Is this the Ease of Doing Business? This cess is also on the machines. It is not on the production. Anybody who owns the machine will automatically be a taxable person. It is the capacity to tax which is a bad thing.

**6THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Thank you very much, Sir.

There were 35 hon. Members who spoke on this Bill. I think, 30 of them spoke yesterday and five of them have spoken now. Sir, by normal course I would have gone back to say a few words about how we have introduced this Bill and so on. But, I understand from Members that there is Private Members' Bill time, and as much as possible, if I can reduce my response, I will try to do it. I will, therefore, avoid going back to talking about what exactly I said yesterday at the time of introduction, and give more importance to responding to the hon. Members. It may appear as if I am abruptly beginning my reply but in order to accommodate the request for Private Members' Bill time, I will start with the responses. I do not

want to do injustice to any Member who has raised any issue, and, therefore, I will focus on that rather than going back to talking about the Bill and its objective and purpose. Some of the questions, which hon. Members have raised, I will try to address them as well in my reply.

So, I am not going back and talk about the purpose of the Bill; it is a cess and not a duty; I am not going into that. But, I will have to, of course, speak on the aims of the Bill. The cess, which gets collected, a part of it will be spent on public health, and the other part of it will go for defence related purposes. Of course, there are Members who have spoken about it as well. So, I am giving a clarification.

The issue of public health is a State subject whereas national defence is a Central subject. It is very clearly defined in the Seventh Schedule of the Constitution. So, in this day and age, where credible defence capabilities are absolutely critical for national defence, we need to raise resources to buffer the defence requirements. Also, the modern conflicts are dominated by precision weapons, autonomous systems, space assets and cyber operations. They are becoming capital intensive. They are becoming such in nature that unless you periodically update the technology, they are not even ready for a modern-day warfare.

From the ramparts of the Red Fort, hon. Prime Minister had said about Mission Sudarshan Chakra, which means, building a wall of security around the country's key locations. So, now the warfare is not just in the borders, but key locations will also have to be protected. Industrial and public sector undertakings are all heavily invested in, and we need to protect them. The enemy should not be given any chance to penetrate. If the enemy does, our Sudarshan Chakra will destroy them. That is the capability we want to bring in.

Sir, you must be aware that during Operation Sindoor, how our three Forces worked together using signals, drones and all kinds of digital technological advances that we have. We had neutralised the targets without our troops even crossing the border.

With our active role, there was no civilian casualty here and across the border. The humanitarian line was also very clear. This is actually the reality of modern warfare. Technology is so advanced that you need to constantly keep updating it. Tech-driven precision was displayed during Operation Sindoor. Precision is the key word in which we need to invest, for which we need resources and we need to understand that it does not come cheap. Therefore, more resources towards

specific objective of strengthening defence will have to be made and cesses are normally those taxes which come with specific objectives stated upfront. That is why, cess is being levied. Therefore, this offers us a feasible mechanism to strengthen both citizen's health and military preparedness.

Now, what is citizen's health? Public health is the State subject, and if money is being provided for public health, it obviously goes to the States in order that they are able to help people stop using these harmful demerit goods or building awareness or supplementing their medical requirement and so on. That is the purpose, intent and also the way in which this cess is being levied and will be used. We are only taxing the demerit goods. This cess is not for anything else. The incidence of this tax is going to remain the same, largely as it is prevailing now.

When I explained the point about excise duty earlier, I explained as to what is the World Health Organisation's affordability index in using items like cigarettes. They are far below the global benchmark, and therefore, we have to increase it so that it does not become affordable for people who are using these demerit goods.

Sir, I want to have a word on the scale of the tax reform. Now, I heard the hon. Members saying that this Government has become so desperate that it wants to raise taxes through such cesses and levy a tax on pan masala, and that too levy tax on pan masala for defence. Have you become so desperate? I just want to respond to them. It is the duty of any Finance Minister to raise revenue so that various competing demands are met. But, here is the Government which has already given away its fiscal space in very many ways within one year of coming in power. Sir, I do not want to do any comparison, particularly, having achieved this kind of a level with the hon. Prime Minister's guidance. Absurd levels of income tax prevailed in this country. There was 95 per cent tax on income. My comparison with that will be absurd. It is because within one year, we gave a huge reduction in income tax. The previous number was Rs. 7 lakh and probably with all the other deductions, it would have come to Rs. 7.76 lakh. The people earning up to Rs. 7.76 lakh had nothing to pay as income tax. There were a lot of speculations, saying we will probably go up to Rs. 8 lakh or Rs. 10 lakh. We went up to Rs. 12 lakh. Today, people probably do not have to pay tax on income of Rs. 12.26 lakh. That is on the one hand.

On the other hand, in the same year, with the approval of the GST Council, I am grateful and I will never miss an opportunity to thank all the members of the GST Council, which agreed for a sweeping change in the GST, we could make items

meant for common man cheaper. No item was excused across the board. Every Member in the GST Council came together to agree for it.

So, that income tax, with no tax till Rs. 12 lakh income, actually has left Rs. 1 lakh crore in the hands of our people. That is a fiscal space I had. I could have made sure that taxes were collected even to that extent. No! That Rs. 1 lakh crore is now in people's hands.

So, at no point in India's history, 1947 onwards, within one year, both direct and indirect taxes have been reduced at this substantial level. I am happy to stand here to say that I had the fullest guidance and support of the hon. Prime Minister that we were able to do it. Now, at this time, when we are bringing a cess on a demerit good, after having given income tax reduction and after having reduced the GST, we are bringing tax on a demerit good but some Members are saying that the Government is so desperate for revenue. I need to give money for Defence. Am I taxing essential commodities of the common people? No. It is only on the demerit goods.

माननीय सभापति**:** मैडम**,** एक मिनट रुकिये । माननीय सदस्यगण**,** अगर सभा की सहमति हो तो प्राइवेट मैम्बर्स बिल इस विधेयक पर सभा के निर्णय के पश्चात् लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य **:** जी हां ।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** I am sure that not even one Member of this House is suggesting that pan masala must be made affordable. (*Interruptions*) वह अलग बात है**,** अच्छी बात है । (व्यवधान) So, they should not enjoy normal tax and no serious argument exists to defend that kind of a thing. So, the money being collected from pan masala is going for defence. Money is fungible. I will collect it, I will use it for Defence, I will use it for road building, I will use it for infrastructure.

**SHRI RAJEEV RAI (GHOSI):** Please give us the details of where the funds are being used.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** I will give you the number wise-details, please wait patiently. I will give you every number on every cess collected and where it has gone. नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट मैम्बर्स बिल लगा हुआ है, लेकिन उसका जवाब तो मिलेगा । (व्यवधान) Sir, therefore, collecting revenue and making sure your nation is well defended, is a right duty of every Government and that is what we are doing here.

I just want to just flag how for want of resources our soldiers were left in the Himalayan cold without boots, without woollens; and without even food

sometimes, our soldiers had to stay at the border. We do not want that situation. We could not even procure artillery guns for a period of 30 years after that episode of Bofors. Nobody had the courage to go and buy anymore because they thought because of that scandal, anybody will mock them and accuse them. So, everybody stayed back, we did not even procure. For 30 years, no artillery gun was procured. And the fear of that image  Defence means kickbacks  made many Ministers not to do anything and not to take any decision. Why? I do not want to get into that vicious environment of defence procurement. Everybody stayed back. But in the process, our Armed Forces were left without defence for themselves. They did not have the guns, they did not have the boots, they did not have the artillery and even for that matter, they did not even have enough ammunition.

So, that was the state. I can go to every detail of who said what at that time. For reasons that we do not have money, we are not able to procure, the hon. Minister had given that statement in this House. He had said, I am not able to procure because I do not have money. I am not going into the details. But everybody knows the moment I say this as to who I am referring to.

So, the capability gap that the Defence suffered from took a long time for restoring that kind of a preparedness of our Armed Forces. The Kargil conflict suffered because of that. Retired Army Generals have said how the Army followed a bottomline approach due to budgetary constraints from the early 1990s. As a result, the Army was holding only 70 to 80 per cent of authorized weapons, ammunition, and equipment. We do not want that stage ever in India back again.

Sir, there are many instances. For the sake of the hon. Members who wanted to quickly finish this and concentrate on the Private Members Business, I will only quote one C&AG Report. The Report came out in 2015, but it pertains to the year 2013. The Army's ammunition reserves were at a crisis level. Against the official requirement of stocking 40 days of war reserves, 125 of 170 ammunition types fell below the 20-day supply. Shockingly, half of all the ammunition types had stocks for less than 10 days of intensive warfare, as of March 2013.

So, that is the level to which our Armed Forces were depleted of their resources. We cannot afford that. Therefore, we want to ensure a consistent, regular, and steady flow of income so that we are able to allocate that for Defence purposes.

There is one other example that always makes me feel very depressed. The 2011 Report by the C&AG painted a very dismal picture of our coastal defence, citing *ad*

*hoc* planning and a huge shortfall in manpower and equipment. The Indian Coast Guard, entrusted with much of the coastal security, was operating at barely half its required strength. Only 65 per cent of the needed patrol vessels were available, and 48 per cent of the required aircraft were in service. So, that is the kind of lacuna we faced. We do not want that situation. We should be able to provide for our Defence far more efficiently and steadily.

Sir, now, I will go over to talking about particular Members concerns. Shri D. Prasada Rao, Shrimati Supriya Sule, and also Dr. Prabha Mallikarjun raised an issue stating that there are no details about the schemes for which the cess will be levied. I think, many others have also spoken in a similar vein, mentioning that there is no clarity on the distribution of the cess among the two objectives stated. I want to clarify that Section 7 (1) of the Bill makes it very clear that the proceeds of the cess are to be used only for two purposes, that are, strengthening India's national security and supporting public health. This actually creates a complete ring-fence framework; and that will actually be implemented for these two purposes.

The Central Government will specifically prescribe the activities, schemes, and programmes whether in the area of national security or public health for which the cess is being utilized. I want to underline the fact that how funds are going to be allocated across objectives will be laid out through the rules, about which Supriya ji specifically had a question. I will explain that.

Several hon. Members like Dr. T. Sumathy, who's here, Dr. Alok Kumar Suman and even hon. Member Supriya Sule had raised this issue. Does the Centre have the right to even impose cess? Where does it come from?

The constitutional power of levying a cess rests entirely in Article 270, Entry 97 of List-1, which authorizes the Parliament, not the Government of the day, to levy a cess for a specific purpose. This is at. The residual entry empowers Parliament to legislate on matters and taxes mentioned elsewhere.

Now, taking it further, the Supreme Court in one of the judgments on Mohit Minerals case passed in 2019 has reinforced that the Centre can levy a cess through the Parliament. But then, the final point was also further raised, saying, You are going to do it all through notification. Will there be a CAG because this money will go into the public fund, the consolidated fund? So, what happens?

Sir, I must humbly submit that a notification in order to levy a certain cess, the rate particularly, is tabled in the Parliament. When the Parliament is in session, we come and say it. When it is not in session, it is laid there for 30 days. It waits for the Members of Parliament to look at it, and they can raise any objection or question or not speak about it. Nothing goes beyond the Parliament on this.

I was even surprised to hear, Will the CAG audit or not? Nothing can happen without the CAG looking at the financial matters. For a cess that is levied through a notification, where the rate is mentioned, approval of Parliament is taken through this Act. The notification comes out separately. But it comes to the Parliament. It gets laid here. There are Parliamentary Standing Committees, Finance, the PAC, the Estimates, internal audit mechanisms, everything exists. So, where is this fear that CAG will not be looking into it? CAG also produces its report. Yes, I have heard Members say it. So, please, utilisation from the Consolidated Fund of India is subject to the highest level of oversight under the Constitution through the Parliament, through the CAG, through the PAC, through the Estimates, and through the internal audits. Nothing escapes from this Parliament when question of the cess happens. So, I want Members to be assured on that. There should not be any doubts in the minds of any Member about, Oh, this is a cess, it is a private domain of the Government. No way. It is a complete domain of the Parliament, and I am answerable here to pass it, get one rate and within that notify it. All expenditures from the CFI, not only collection, are also subject to the CAG.

Then, I move to Dr. Alok Kumar Suman, Dr. Prabha Mallikarjun and D. Prasada Rao, who said the structure and certain provisions like fixed cess, a cess on production capacity rather than actual production, may open up a Pandora's box and be detrimental to the sector. The sector is highly evasion prone. It is already taxed at the highest rate by the GST at the consumption level. But that highest rate is not good enough. It is 40 per cent, and GST has a cap. No item can be taxed beyond 40 per cent. That is one thing.

The other is, what is being produced is far higher than what comes out or capacities exist, whether they come out or not, that is where the question of evasion comes. That is why this is an evasion prone sector. Therefore, we did not come out with production capacity as a new parameter based on which the cess can be levied. Even the Central Excise tax gets levied on the production capacity.

It has been existing for a very long time. Excise law in this country is old, since 1944. So, the capacity based taxation is not new. Courts have also recognised that

this is an evasion prone area  machine driven sectors such as chewing tobacco, pan masala. Actual production was difficult to measure and therefore, capacity linked levy as an administratively sound and legally valid method for collecting duty, has been established even in the courts. So, this machine based duty is not new but rather an established mechanism previously applied for tobacco and pan masala sector also.

Sir, then Dr. Sumathy had raised this issue that the situation under which tax can be doubled needs to be clarified upfront and the provision mandating no requirement to come to the Parliament seems arbitrary. No requirement to come to the Parliament does not exist, Madam. We have to come to the Parliament. We have to lay the notification. (*Interruptions*) पहले सेस की एप्लीकेशन के लिए परमिशन लेते हैं, फिर रेट तय करने के समय नोटीफिकेशन होता है । I am sorry. My Hindi is very lay. (*Interruptions*) भाई साहब, ऐसे होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन सॉरी।...(व्यवधान) मैं डांट नहीं रही हूं । मेरी हिंदी कमजोर है । ऐसा नहीं होता है - यह मैंने कह दिया। फिर मैं सोचने लगी, शायद लैंग्वेज की मर्यादा । Alright. That is okay. So, the power to double the tax rate is only for emergency doubling. Accordingly, the provision has been incorporated in the Act for prior sanction of the Parliament. Similar powers exist in other taxation laws also. And what we are doing now is nothing new or nothing unique. Moreover, this Section mandates that we can do it in public interest only. So, we cannot be doing it just for some frivolous reason.

Sir, again Dr. Prabha Mallikarjun, Supriya Sule Ji, and Shri Prasada Rao from TDP said the power to add new goods to the Schedule without requiring to come to the Parliament seems arbitrary and appears to be undermining the parliamentary processes. We are seeking the approval of the Parliament for notifying more goods to the Schedule. That is a power which we are seeking and this will be done through notification.

Again, the notification comes, places itself, we place it in the Parliament and the Members are given at least 30 days to have a look at it, and so on. Now, what are these goods? Now, what are these goods which will be added in the future, if at all? For example, Sir, pan masala that is currently covered is the one with tariff classification 21069020. That is the HSN code number for pan masala. There may be many different variants which may come up in the future due to ingenuity of the industry. This should also be brought within the ambit of the levy. This would be notified by the Central Government without the requirement of coming to

Parliament every time, each time. We notify that this seems to be very close to this 21069020.

Therefore, this should also be covered under the cess, the intent of which is already mentioned. It is a demerit good. I cannot bring, let us say shampoo into this. I cannot bring *besan* or *atta* into this. Demerit good which has probably some semblance with pan masala or is a pan masala becomes evolved, it becomes something else. There is a metamorphosis. (*Interruptions*)

The objective itself says it is only a demerit on pan masala. You want the word demerit put onto it. This would be notified by the Central Government without the requirement of coming to Parliament. That is one thing I want to explain even as I am responding to Dr. D. Prasada Rao. Metamorphosis is a product of ingenuity. What appears today as pan masala can appear differently tomorrow, with a different name but am I then not going to be able to collect tax on it? I need to.

On this issue of demerit, the Statement of Objects and Reasons makes it clear that the proposed cess is carefully confined to the production capacity of a specific demerit good, namely pan masala. The intent is unambiguous. The cess is limited to demerit goods such as pan masala and is being applied only where there is a clear fiscal space to do so. (*Interruptions*)

**SHRI SASIKANTH SENTHIL :** Madam, where is this word demerit added? The word demerit is not there. (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** I have heard you. Would you want to listen to me for a minute? I have heard you. In fact, just as you responded when you were speaking as I came in, for every issue you have raised even the previous one, because you mentioned the previous I have responded. And even now on this Bill, I am sorry to say you have misled the House, and I am answering. There is absolutely no intention to step into the domain of GST taxation, which remains exclusively with the GST Council. The design of the levy fully respects the constitutional scheme while enabling the Government to mobilize resources for priority national objectives.

Dr. Alok Kumar I am not sure if he is here asked whether the cess could be imposed on advertising of specified goods. Advertising is a service and is subject to GST. It is already subjected to GST. There is no proposal to include advertising in this cess. How will there be a reduction in the consumption of the commodity?

Again, Dr. Sumathy, Dr. Alok Kumar, and Dr. Prabha Mallikarjun raised this. Once the GST compensation cess comes to an end, the effective tax incidence on pan masala which is currently about 88 per cent, comprising 28 per cent GST and 60 per cent compensation cess will change. The 60 per cent compensation cess will end. The 28 per cent GST does not exist. It will have to move to 40 per cent, which is the tax for demerit goods. So, it goes to 40 per cent. From 88 per cent, it will come down to 40 per cent. It falls sharply.

The GST Council approved the proposal to increase the GST rate to 40 per cent, which will be effective on a date in the near future, once the compensation cess ends. If the tax incidence comes down, it will have the unintended consequence of making pan masala considerably more affordable. We cannot afford to leave it there. There was a genuine concern that this unintended outcome greater affordability of pan masala, which is a highly addictive, low-cost demerit good would not only compromise public health objectives, but also result in loss of Government revenue. So, we have a fiscal space, and therefore we cannot allow it to become cheaper and yet lose revenue. We want it not to become cheaper, but also to ensure the revenue space is filled. The name of the cess was a matter which was also raised.

A question was raised about whether the pan masala consumers are going to finance the national defence. It is neither in the design nor in the intent. As I said, tax can be collected, it will be used, money is fungible.

Sir, there was also this observation which I think is very important and for which I will respond: The officers have been provided sweeping discretionary powers like inspection and abatement. This will increase Inspector Raj. It was a very legitimate question that many hon. members had. I want to respond, Sir.

Pan masala has long been one of the most evasion prone sectors. Even genuine manufacturers repeatedly express concern about spurious and illegitimate supplies that distort the market.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

In such a situation, it becomes essential to equip the administration with adequate tools so that fair and uniform standard of compliance is maintained across the sectors. So, this protects revenue and also ensures a level playing field. Let me expand on how this is going to work. Machine capacity based system will be implemented through a modern technology enabled and non-intrusive oversight

mechanism. It will focus on transparency, objective parameters, minimal disruption to manufacturing activity, and so on. So, there are three clear layers.

First, it will be on a self-declaration. The manufacturer himself or herself says what is the capacity and speed at which their machine is running. They will also be allowed that if they need to change anything in the first declaration that they give, they will be in a position to change any addition or correction that they have to do. It is at that stage, it will be very quickly verified if their statements are all tallying and everything else.

The second stage would be technology supported and a continuous oversight. The third stage would be risk based enforcement checks. So, after the initial verification, the system moves away from physical supervision towards technology driven monitoring using tools such as CCTV coverage, tamper proof sealing and other automated safeguards. Further to strengthen automation and reduce discretion even further, the design also anticipates phased adoption of motion sensors and integration with BIS standards in the future.

Beyond this, there are also elaborate appellate provisions with judicial oversight enshrined in the proposed legislation where the original orders can be first reviewed or revised and then appeals would lie with the appellate authority and then the appellate tribunal and then finally the High Court and if necessary the Supreme Court. So, every layer of appeal is respected and no denial of natural justice is even thought through.

Sir, all these proposed levies are after a detailed study of the entire manufacturing process because there were concerns voiced by many hon. Members saying a fixed levy on machine irrespective of the produced quantity will be detrimental for the small manufacturers. I want to address that concern of hon. Members about the small manufacturers. We did a detailed study on the ground.

Sir, The levy is designed based on the machine capacity taking into account the speed of production and the weight of the individual packing that is produced by the said machine.

**16.00 hrs**

Therefore, each owner of the machine will be charged based on the size and quality of the machine. However, first of all, in the GST itself, small units come under

composition. So, they do not have taxes levied on them if they are below a certain number. We have a progressive structure here.

If I were to take an example, for a machine producing up to 500 pouches per minute with each pouch having a certain grammage, they will have to pay a certain amount. So, like that in graded fashion we have assessed each of the machine, their speed and the total grammage that will go into each of the pouches and then decided on the tax. However, I need to underline the fact that there is a separate category for manual processing. So, the small units come under it.

What special steps have been taken for those taxpayers who are into manual production? I will just take a minute to explain this point. Based on a detailed study of the sector, the amount of cess for a unit which is engaged in wholly manually processed pan masala, hand-made has to be kept at Rs. 11 lakh per factory. This is only 10 per cent of the lowest cess amount applicable on the machine-based process. So, the wholly man-made items are being given a very concessional treatment so that they are not affected. We are not encouraging people to shift into manual process and still be producing pan masala. So, there is an element of deterrent. This will ensure that a unit engaged in handmade processes is not discouraged, but at the same time, they shall not be incentivised.

The final bit is very important on the cess collection till now. It was said that: You are bringing one more cess. What happens to the cesses that were collected earlier? Did you distribute it? You are sitting with a lot of collected cess which is not given. I will give the details.

First of all, cesses are not new. Article 270, I said, gives the Union the power to levy cesses. But cess is always collected for a specific purpose. Normally, cesses are not devolved to the States, but in this one I clearly have said that there will be a portion of it being spent on public health, and since public health is a State subject, the money will go to the States.

Let us look at the pre-2014 cesses just to set the context. There were at least four cesses collected during pre-2014. So, it is not as if in 2014 we came into power, and Prime Minister Modi thought that do not give money to the States and collect cess. No, cesses existed even before. Cess on crude oil had been imposed under the Oil Industry Development Act, 1974. This cess has been prevalent since 1970s. The Oil Industry Development Fund (OIDF) was not created until 2023-2024. So, the Government of India created the OIDF and an amount of Rs. 17,730 crore and Rs.

19,376.03 crore was provided for transfer to the OIDF in RE of 2024-2025 and BE of 2025-2026.

The National Calamity Contingent Duty has been levied from 2001 and this is for financing disaster-related expenditure. I do not have the total that was collected at that time. I am sure that we will be able to gather it and leave it at the Table here. The Road and Infrastructure Cess has been levied since the year 2000.

This cess has been collected on imported manufactured motor spirit, commonly known as petrol and high-speed diesel under Central Road Fund and later that was called Central Road and Infrastructure Fund Act. An amount of Rs. 11,34,764 crore during 2014-15 to 2025-26 has been transferred under this cess, while the collection was only Rs. 11,11,692 crore during the same period. The amount of collection is Rs. 11,11,000 crore, whereas Rs. 11,34,000 crore has been distributed.

There has been an evolution in health and education cess. Primary education cess has been there since 2004-05, which later on became Secondary and higher education cess. That was added on the top of the existing cess in 2007-08. Merging the above two cesses, new health and education cesses, four per cent on income tax was introduced in 2018-19. I will read the numbers which are of interest for hon. Members. The Government has transferred an amount of Rs. 6,49,459 crore during 2014-15 to 2025-26 against a collection of Rs. 6,07,573 crore, much more than what was collected. These are the cesses which existed before 2014. I would like to give you a picture of the cess post 2014-15. I will come to the GST compensation cess a bit later.

Agriculture Infrastructure and Development Fund was introduced in 2021-22. The Government has so far transferred Rs. 3,77,214 crore against the collection of Rs. 3,87,226 crore. So, if the feeling is, more cess are being brought now, more cess are being collected now, less is being given to the States, I want to underline the fact.

I want to now come to cess as a percentage of Gross Tax Revenue (GTR), without the compensation cess. Why will I not include compensation cess? It is because the compensation cess completely went to the State, Centre could not even take one penny out of it. So, I am not even including that. Without including that, 6.1 per cent was the cess as a percentage of Gross Tax Revenue, and that is stated in BE of 2025-26, the current years Budget. This is far lower than the cess as a percentage of GTR. If I take 2010-14, during those years, how much was cess to GTR? At that

time, from 2010-2014, it was seven per cent, whereas what we are doing now is 6.1 per cent. हमारे ऊपर गाली-गलौज होता है कि उन्होंने सात परसेंट कलेक्ट किया, लेकिन आप 6.1 परसेंट कलेक्ट कर रही हैं । आप सेस कलेक्ट कर रही हैं और इसे आप ही रख रही हैं । यहां बात करने से पहले इनको डेटा देखना चाहिए । आपने सेस के ऊपर प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं इस विषय पर बोल रही हूं ।

I mentioned about OIDF. I just want to highlight the fact. हमारा जवाब आपको कड़वा और खट्टा लग रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसे शॉर्ट कर लीजिए । मैं इसे शॉर्ट कर लेती हूं, क्योंकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही है । प्राइवेट मेम्बर्स बिल सहित सभी बातें सामने ही हुई हैं । आपको सडेन्ली ही प्राइवेट मेम्बर्स बिल के ऊपर इतना ध्यान कैसे आ रहा है, क्योंकि डेटा कड़वा है ।

Sir, I just want to add the last one thing which I said, I have not given the number.

Now, I come to the National Calamity Contingent Fund (NCCD), which is also a cess. It is a kind of a duty which is collected. How much was collected under it? It was Rs. 68,656 crore. How much was transferred under the NCCD? It was Rs. 72,993 crore.

हमने भी सेस कलेक्ट किया, ज्यादा दिया है, हम रख नहीं रहे हैं । Final compensation cess collected is Rs.9,45,237 crore. पूरा का पूरा स्टेट को जाता है, केन्द्र में कुछ भी नहीं रहता है, बचा हुआ पैसा भी । How much has been paid to the States? Rs. 9,33,920 crore, lesser than Rs. 9,45,237 crore because there are two States which have not given us the AG certificate yet. Which are those States? Arunachal Pradesh and Manipur. If they come, the leftover compensation cess also will go to them. I will not have one penny kept under the compensation cess. मंत्री जी आपके स्टेट का बताइए । I just want to highlight that every cess collected has gone back. We have given much more than what we have collected. We have not kept and so would be the case with this cess also. We have already very clearly said that it will go for public health considerations. Public health is a State subject. The money will go to the State Governments. If hon. Members have a doubt that we are bypassing the Parliament, that is not at all the case. The notification will come here for rates and it is a law which will be clearly scrutinized. The revenue collected and the revenue spent will all be scrutinized by the C&AG. Thank you.

माननीय अध्यक्ष **:** अभी क्या और सुनना चाहते हैं । आप बताइए । मनीश जी, क्या आप और सुनना चाहते हैं?

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूर्ण करने के लिए संसाधनों के संवर्धन और मशीनों के संस्थापन या अन्य प्रक्रियाओं पर, जिनसे विनिर्दिष्ट माल विनिर्मित या उत्पादित किए जाते हैं, उक्त प्रयोजनों

के लिए उपकर के उद्ग्रहण और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

**CLAUSE 2** Definitions

माननीय अध्यक्ष **:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**2SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** Sir, I beg to move:

Page 3, *for* lines 2 to 4,-

*substitute* (*p*) specified goods means the goods as specified in Schedule I to this Act, and such other goods as Parliament by a law, specify;.(1)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>खंड *2* विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड *3* और *4* विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

**CLAUSE 5** Member of computation of cess

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**4DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** Sir, I beg to move:

Page 4, *for* lines 21 to 25,-

*substitute* (*4*) Where the specified goods are manufactured or produced by a taxable person wholly by manual process without the aid of a machine, the cess levied and collected for each factory shall be at the monthly amount specified in column (4) of Table 2 of Schedule II:

Provided that where the taxable person employs fewer than twenty persons in such manual process, the cess levied and collected from such factory shall be reduced by seventy-five *per cent*.; and where the number of persons employed are between twenty and fifty, the cess levied and collected shall be reduced by fifty *per cent.*. (2)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *5* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 6** Power of Central Government to increase amount of cess in special circumstances

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ.टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** Sir, I beg to move:

Page 4, line 38,-

*after* Central Government

*insert* , after due consultation with the States or the Union Territories, as the case may be,. (3)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री डी**.** एम**.** कथीर आनंद - उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है :

कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *6* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 7** Purpose of levy of cess.

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** Sir, I beg to move:

Page 4, line 50,-

*after* law in this behalf,

*insert* shall be shared with the States and Union Territories and. (5)

Page 5, line 1,-

*after* Central Government

*insert* , after due consultations with the States/Union Territories,. (6)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री ससिकांत सेंथिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**5SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR):** Sir, I beg to move:

Page 4, *after* line 51,-

*insert (2A)* Notwithstanding anything contained in this Act, fifty per cent. Of the net proceeds of the cess shall be distributed between the Union and the States in accordance with the provisions of Article 270 of the Constitution of India.. (23)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *7* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *8* विधयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 9** Declaration to be filled by taxable Person.

माननीय अध्यक्ष **:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**6** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील **(**सांगली**) :** सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि खुद मैडम ने कहा है कि राज्यों के साथ रेवन्यु शेयर करेंगे । इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह एक्ट का हिस्सा बने । So I am moving it, Sir.

Sir, I beg to move:

Page 6, line 6,-

*after* Joint Commissioner

*insert* , who shall record in writing the reasons for such verification,. (7)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *9* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 10** Payment of cess and returns.

माननीय अध्यक्ष **:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**8SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** Sir, I beg to move:

Page 6, line 22,-

*after* prescribed

*insert* and the self-assessment made shall be final unless the proper officer issues a notice under section 16 within two years from the end of the relevant month,. (8)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *10* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *11* से *13* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**CLAUSE 14** *Access to business Premises.*

माननीय अध्यक्ष **:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 14 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *14* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *15* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 16** Determination of cess not Paid or Short Paid or erroneously refunded.

माननीय अध्यक्ष **:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):** Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *16* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *17* से *19* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**CLAUSE 20** Offences by companies.

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**9DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** Sir, I beg to move:

Page 11, line 49,-

*for karta*

*subsitute* manager of a Hindu Undivided Family. (11)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 20 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *20* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *21* से *23* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड *24* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**CLAUSE 25** Confiscation of Specified goods or machines.

माननीय अध्यक्ष **:** श्री ससिकांत सेंथिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**20SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR):** Sir, I beg to move:

Page 14, *after* line 43,-

*insert* Provided that no final confiscation of goods or machines shall take effect unless the person concerned is convicted by a competent court.. (24)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल जी द्वारा खंड 25 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

कि खंड 25 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *25* विधेयक में जोड़ दिया गया।

**CLAUSE 26** Power to arrest.

माननीय अध्यक्ष**:** श्री ससिकांत सेंथिल, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR):** Sir, I beg to move:

Page 15, lines 9 and 10,-

*for* may,by order, authorise

*substitute* may, with the prior sanction of a Judicial Magistrate Of the First Class, by order, authorise. (25)

माननीय अध्यक्ष**:** अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा खंड 26 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *26* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *27* और *28* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**CLAUSE 29** Appeals to appellate authority.

माननीय अध्यक्ष**:** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**21** श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील **(**सांगली**) :** सर, विनती यह है कि अपील का पीरियड थोड़ा बढ़ाया जाए । I am moving it.

Sir, I beg to move:

Page 16, *after* line 34,-

*Insert* Provided that the period of appeal may be extended by the appellate authority by a further period of three months for sufficient reasons recorded in writing. (17)

माननीय अध्यक्ष**:** अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष**:** डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

**22DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** Sir, I am not moving it.

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

कि खंड 29 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *29* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *30* से *33* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**CLAUSE 34** Power of Central Government to amend schedule I.

माननीय अध्यक्ष**:** श्री ससिकांत सेंथिल, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**3SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR):** Sir, I am moving the amendment. I beg to move:

Page 19, lines 29 and 30,-

*for* , as soon as possible after it is issued, be laid before each House of Parliament

*substitute* not take effect unless approved by a resolution passed by both the Houses of Parliament.(26)

माननीय अध्यक्ष**:** अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा खंड 34 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

कि खंड 34 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *34* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *35* से *39* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

पहली अनुसूची

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड *1,* अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

**4SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I rise to move:

That the Bill be passed.

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है :

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———